DISH DOCTOR

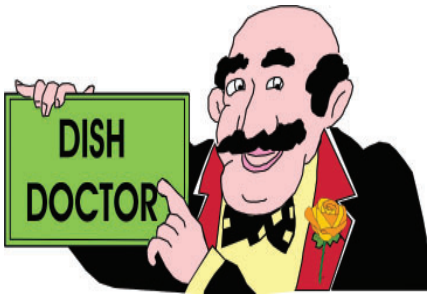

Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.

Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing,3rd Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or
Email: manoj.madhavan@nm-india.com. Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Queries To: +91-91082 32956

OTT REGULATION

Q: What is the current status on the OTT Regulation?

Zakir Hussain,
Media Consultant, Hyderabad

Ans.: India's efforts to regulate OTT platforms are currently focused on the Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023, which is intended to modernize the country's broadcasting laws. This draft bill is designed to bring OTT platforms and digital news services under a unified regulatory framework. It will replace the older Cable Television Networks (Regulation) Act of 1995 and address newer broadcasting technologies.

Key provisions in the bill include the establishment of content evaluation committees for self-regulation and a Broadcast Advisory Council to advise on potential violations related to program and advertisement codes. The bill also includes measures for inclusivity, such as promoting subtitles and audio descriptors for people with disabilities.

However, challenges remain. Critics argue that the bill may impose excessive control, especially over certain digital platforms, and there is ambiguity around how different types of content—such as user-generated social media content versus professional OTT content—will be regulated. The bill is still under discussion, and ministries are working on finalizing clear guidelines to reduce regulatory overlap and provide a robust framework.

ओटीटी विनियमन

प्रश्नः ओटीटी विनियमन पर वर्तमान स्थिति क्या है?

जाकिर हुसैन,
मीडिया सलाहकार, हैदराबाद

उत्तरः ओटीटी प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के भारत के प्रयास वर्तमान में प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, **2023** पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य देश के प्रसारण कानूनों का आधुनिकीकरण करना है। यह मसौदा विधेयक ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार सेवाओं को एकीकृत नियामक ढ़ांचे के तहत लाने के लिए बनाया गया है। यह पुराने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम **1995** की जगह लेगा और नयी प्रसारण तकनीकों को संबोधित करेगा।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों में स्व-नियमन के लिए सामग्री मूल्यांकन समितियों की स्थापना और कार्यक्रम और विज्ञापन कोड से संबंधित संभावित उल्लंघनों पर सलाह देने के लिए एक प्रसारण सलाहकार परिषद् की स्थापना शामिल है। विधेयक में समावेशिता के उपाय भी शामिल हैं, जैसे विकलंग लोगों के लिए सब टाइटिल और ऑडियो डिस्क्रिप्टर को बढ़ावा देगा।

हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक विशेष रूप से कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक नियंत्रण लगा सकता है और इस बात को लेकर अस्पष्टता है कि विभिन्न प्रकार की सामग्री – जैसे कि उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सोशल मीडिया सामग्री बनाम पेशेवर ओटीटी सामग्री को कैसे विनियमित किया जायेगा। विधेयक पर अभी भी चर्चा चल रही है, और मंत्रालय विनियामक ओवरलैप को कम करने और एक मजबूत ढ़ांचा प्रदान करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं।